पुस्तक समीक्षा

आधुनिक जयपुर के निर्माण का प्रमाणिक अध्ययन: ''जयपुर रियासत का आर्थिक इतिहास''

लेखक : रश्मि मीना

प्रकाशक : राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर

प्रकाशन वर्ष : :2021

मूल्य : 995 रूपये

डॉ. रश्मि मीना की पुस्तक ''जयपुर रियासत का आर्थिक इतिहास'' ब्रिटिश काल मे राजपुताना रियासतों में हुये परिवर्तनों की बहस मे नया योगदान है। इस पुस्तक की वैचारिक जमीन डॉ. मीना ने अपनी पीएच.डी., राजस्थान विश्वविद्यालय, के दौरान तैयार की। यह पुस्तक उनके शोध प्रबन्ध का संवर्धित एवं संशोधित रूप हैं, जिसे उन्होंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में अध्यापन के दौरान पूरा किया है।

19वीं शताब्दी में जयपुर रियासत के कछवाहा शासकों में आपसी संघर्षों, विभेदों के कारण आमन्त्रण स्वरूप हुये मराठा आक्रमणों ने इस रियासत मे आमूल-चूल परिवर्तन किये। फलस्वरूप कछवाहा शासकों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी, जो कि तत्कालीन भारत में सर्वोच्च सत्ता थी, के साथ संधि की एवं स्वयं एक अधीनस्थ की भूमिका में रहना स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में जयपुर रियासत की अर्थव्यवस्था पर क्या दूरगामी एवं स्थायी प्रभाव पड़े एवं इन प्रभावों का राज्य के शासकों एवं जनता ने किस तरह से स्वीकार-प्रतिरोध किया यह जानने के लिए डॉ. रश्मि मीना की पुस्तक बहुत उपयोगी है।

पुस्तक का अध्ययन काल 1857 की क्रान्ति के पश्चात् से प्रारंभ होकर स्वतन्त्रता प्राप्ति तक का है। छह अध्यायों एवं दस परिशिष्टों में विभक्त यह पुस्तक अपने प्रामाणिक एवं विश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण से शोधार्थियों के लिए उपयोगी बन पड़ी है।

जयपुर के महाराजा रामसिंह द्वितीय (1835-80) के काल से प्रारंभ इस पुस्तक में आमेर की स्थापना से मुग़लकाल के अन्त तक क्रमवार विकास के दौर को प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थियों के लिये राजस्थान के इतिहास में सामन्तवाद की जटिलताओं को समझना सामान्यत: कठीन ही रहा है, परन्तु लेखिका डॉ. रश्मि मीना द्वारा राजस्थान में सामन्तवाद का उद्भव एवं उसकी यूरोपीय सामन्तवाद के साथ सारगर्भित तुलना ने इस जटिलता को सुगम बना दिया है। (पृ. 22-23)

जयपुर राज्य में जागीरी क्षेत्र का विभाजन कछवाहा राजवंश से सम्बन्धित सरदारों/ठिकानेदारों में बंटाव के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली आय, जो वार्षिक कर या तन थी, राज्य के लिये न केवल राजस्व स्रोत थी बल्कि भाई-बंट रिश्ते पर आधारित होने से सभी जातिबन्धुओं को प्रशासन में सम्मानीय स्थान प्रदान करने की दृष्टि से भी रोचक व्यवस्था थी। यह व्यवस्था मजबूत शासक के समय तो स्थाई थी परन्तु आर्थिक-राजनीतिक परिस्थिति एवं शासक के कमजोर होने की स्थिति में महत्वाकांक्षी जागीरदारों को अपनी तलवार के बल पर विस्तार करने का अवसर भी देती थी जैसे माचेड़ी के शासक प्रतापसिंह द्वारा खालसा क्षेत्र पर अधिकार कर अलवर राज्य की स्थापना करना। (पृ. 26)

प्रथम अध्याय में जयपुर राज्य की भौगोलिक अवस्था, गद्दीनशीन राजाओं के कालक्रम अनुसार राज्य वर्णन एवं कृषि भूमि का विभाजन एवं अधिकार के बारे मे उल्लेख किया गया है।

द्वितीय अध्याय में खालसा क्षेत्र में रबी एवं खरीफकी फसल के रूप में बोई जाने वाले विभिन्न नकदी व खाद्यान्न फसलों के उत्पादन, मूल्य आदि का अकंन है। इन फसलों हेतु सिंचाई व्यवस्था के लिये किये गये प्रयासों जैसे बांध निर्माण, कुओं, तालाबों आदि के निर्माण वास्ते राज्य सहायता का अध्ययन है। लेखिका डॉ. मीना द्वारा प्रमाणिक प्राथमिक स्रोत, जयपुर स्टेट एडिमिन्सटेटिव रिपोर्ट के आधार पर कृषिगत फसलों का विवरण सारणीरूप मे प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय तृतीय में भू-राजस्व एकत्रित करने के लिये इजारा व्यवस्था को जयपुर रियासत मे लागू करने के विभिन्न फलक जैसे इजारा अवधि, वंशानुगत एवं परंपरागत अधिकार, अधिक वसूली होने से ग्रामीणों के शोषण के बारे में उल्लेख हैं। 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में रियासत में इजारा प्रणाली की जगह रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई जिससे इजारा प्रणाली का प्रभाव कम तो हो पाया परन्तु

पूर्णतया समाप्त नहीं होने के कारणों का तार्किक अन्वेषण डॉ. मीना द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

ग्रामीण कर व्यवस्था जैसे जटिल बिन्दु को डॉ. मीना ने प्रबन्ध, भूमि विभाजन तथा बंटाई पद्धति आदि के माध्यम से सरलीकृत रूप में प्रस्तुत किया है। देशज कर शब्दावली ''माल पटवारा'', ''पहरावनी'', ''शहना-की-घूघरी'' के प्रायोगिक अर्थ भी स्पष्ट किए गए हैं। (पृ.60-61) इसी आधार पर जयपुर रियासत में कृषकों पर लगने वाली शोषण स्वरूप 'लाग-बाग' ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कैसे नकरात्मक प्रभाव डाला, जिससे कृषि उत्पादन कम हुआ, को स्पष्ट किया गया है।

प्राथमिक स्त्रोत 'जयपुर एडिमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट' के आधार पर डॉ. मीना ने बीसवीं सदी की जयपुर रियासत के खालसा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सुधार हेतु किये गये प्रयासों जैसे ग्रामीण विकास योजना (पृ.77) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम (पृ.80) Grow More Food And Fodder Camping (पृ.87) पचांयत बोर्ड गठन (पृ.88) का तथ्य आधारित विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

अध्याय चतुर्थ में जयपुर रियासत की प्रमुख जागीर शासनगत वंशों के साथ सेवाओं के आधार पर दी गई जागीरों के प्रकारों को रेखांकित किया गया है जैसे चकोटी, अलूफा खानगी जागीर आदि (पृ.94-95)। जागीरदारों द्वारा राज्य रियासत के साथ सहयोग और अवहेलना के सम्बन्धों को लेखक द्वारा सावधानी एवं उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया हैं, जो पुस्तक की उपयोगिता में अभिवृद्धि करता हैं। आर्थिक प्रबन्धन के अन्तर्गत जागीरों की आमदनी व खर्च को खेतड़ी ठिकाने के आंकड़ों पर सुलभ रूप से प्रस्तुत कर अच्छा उदाहरण अंकन किया गया है।

पुस्तक 20वीं सदी के प्रथम उत्तरार्द्ध में जागीर क्षेत्रों मे अवस्थित कृषक जातियों द्वारा नवीन प्राप्त राजनैतिक जागृति के कारण जागीरदारों के अत्याचारों के विरूद्ध किये गये प्रयासों को प्रस्तुत करती हैं एवं इन्ही नवजागरणीय प्रयासों के फलस्वरूप ही **राजस्थान भूमि सुधार जागीरदारी अधिग्रहण अधिनियम** स्वतंत्र राजस्थान में पारित हुआ था (पृ.166)। राज्य में लगने वाली 'लाग-बाग' ने राजस्थान के स्वतन्त्रता संग्राम के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जयपुर रियासत द्वारा लगाई गई 32 तरह की लाग-बाग को डॉ. मीना ने उल्लेखित कर कृषको पर हुये शोषण की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की है।

अध्याय पंचम में नमक की सन्धियों के आधार पर जयपुर रियासत एवं अंग्रेजों के मध्य सम्बन्धों का विश्लेषण किया गया है। आधुनिक जयपुर के निर्माण में मध्यम एवं छोटे आकार की 370 फेक्ट्रीयों के योगदान को रेखांकित कर स्वतन्त्र भारत में औद्योगिक जयपुर की स्थिति को पुस्तक में स्पष्ट किया गया है। बीसवीं सदी के तीसरे-चतुर्थ दशक में विभिन्न बैंकों ने अपनी शाखायें जयपुर में खोली, जो व्यापारियों को ऋण उपलब्ध करवाने में सहायक रही। डॉ. मीना द्वारा मध्यकाल से जयपुर के आधुनिक राजस्थान की राजधानी बनने तक के ऐतिहासिक परिवर्तन को अपनी पुस्तक में दस्तावेजीय प्रमाणों के आधार पर विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत किया है।

डॉ. मीना द्वारा प्राथमिक स्त्रोतों जैसे रेवेन्यू एवं ज्यूडिशियल, सर्वे व सेन्टलमेन्ट रिकॉर्ड के आधार पर आधुनिक जयपुर रियासत के आर्थिक विकासक्रम को प्रस्तुत किया है। मूल स्त्रोतों का उपयोग इस पुस्तक की आत्मा है। लेखिका द्वारा पुस्तक में दस परिशिष्ट को जोड़कर पाठकगण के लिये तथ्यों को जानने में सुलभता प्रदान की है। भाषा की दृष्टि से यह पुस्तक इतिहास के विद्यार्थियों के लिये सहज एवं परिष्कृत हैं। शोधार्थीयों एवं विद्यार्थियों हेतु उपयोगी इस शोध कार्य को दृष्टिगत रखते हुये राजपुताना की अन्य रियासतों हेतु भी ऐसे शोध प्रकाश में आने चाहिए। डॉ. रश्मि मीना को जयपुर रियासत के आर्थिक इतिहास अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिये साधुवाद। उन्नत पुस्तक प्रकाशन के लिये राजस्थानी ग्रन्थागार बधाई के पात्र है। डॉ. मीना का यह श्रम साध्य कार्य भविष्य में रियासती राजस्थान के अध्ययन का मार्ग प्रस्तुत करेगा।

समीक्षक : डॉ. नितिन गोयल
निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार,
बीकानेर (राजस्थान)